सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की वापसी की तैयारी शुरू कर दी
Page-04

tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में बोले यश, ट्रेलर रिलीज टली
Page-05

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।इसी बीच सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, जो अब व्यापक चर्चा का केंद्र बन गया है।

NEET पेपर लीक पर संसद में हंगामा

संशोधन विधेयक पेश लेकिन चर्चा टली

NEET प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए लाए गए महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी चार बार बाधित होने के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालिय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों पर कड़ी रोक लगाने के लिए कानून को और सख्त बनाना है।

हालांकि, विपक्ष के विरोध के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लंबे समय से सभी राजनीतिक दल परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए

- सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई।
- NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।

प्रभावी कानून की मांग कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी सांसदों से चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह देश के युवाओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा अहम विषय है, जिस पर सभी पक्षों को अपने विचार रखने चाहिए। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर कोई टिप्पणी नहीं की।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से इस विधेयक पर चर्चा करने का आग्रह कर रही है। उन्होंने कहा कि जो दल लंबे समय से NEET पेपर लीक पर बहस की मांग कर रहे थे, वही अब चर्चा से बच रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाना चाहती है और देश के युवा संसद की कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं।सूत्रों के अनुसार, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक पर चर्चा कराने को लेकर सहमति बन गई है। ऐसे में संभावना है कि मंगलवार को लोकसभा में इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर विस्तृत बहस शुरू हो सकती है।

पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने तालियों से किया स्वागत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधान मुस्कुराते हुए नजर आए और पार्टी सांसदों से गर्मजोशी से मिले। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि शायद यह पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने बिना किसी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या अन्य आरोप का सामना किए केवल राजनीतिक परिस्थितियों के चलते इस्तीफा दिया है।संसद में स्वागत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचे और उनके इस्तीफे पर सहानुभूति जताते हुए कहा, "ऐसा होता रहता है।" इस पर प्रधान ने जवाब दिया, "कुछ नहीं हुआ। मैं ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता हूं, एसी कमरे में बैठकर काम करने वाला एक्टिविस्ट नहीं।" उनके इस बयान को बीजेपी नेताओं ने आत्मविश्वास का संकेत बताया और कहा कि वह भविष्य की राजनीतिक जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी में उनकी अगली भूमिका को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ओडिशा के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी संगठन और चुनावी रणनीति से जुड़े कई अहम दायित्व पहले भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें जल्द ही कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। गौरतलब है कि NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कर रही थी। हालांकि, संसद में उनके स्वागत और आत्मविश्वास भरे अंदाज ने यह संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व अब भी उन पर भरोसा बनाए हुए है।

सीवान छात्र आंदोलन

AK-47 लहराने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई, कांस्टेबल निलंबित

पटना, 27 जुलाई बिहार के सीवान जिले में 25 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो के प्रसारित होने के बाद हुईहै जिसमें पुलिस कांस्टेबल छात्र प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, पीटीआई- इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पूरण कुमार झा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''वीडियो में दिखाई दे रहा कांस्टेबल जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) में तैनात है जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।'' हालांकि, उन्होंने कांस्टेबल की पहचान जारी नहीं की है। झा ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ''यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल ने किन परिस्थितियों में एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया।'' उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को गोली नहीं चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक और राज्य में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आहूत 'बिहार बंद' के समर्थन में वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने 25 जुलाई को कई जिलों में प्रदर्शन किए थे। इस दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। यह बंद पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया और भोजपुर में हिंसक हो गया था, जबकि समस्तीपुर, नवादा, नालंदा, मधुबनी और शेखपुरा समेत कई जिलों में हल्के विरोध-प्रदर्शन हुए थे। पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया था कि 'बिहार बंद' के दौरान सीवान में पुलिस ने छात्रों पर एके-47 से सीधे गोलीबारी की। उन्होंने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहराया था।

सोनम वांगचुक ने पहला वीडियो जारी किया

मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम से छुट्टी मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना पहला वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे और इसके बाद पहाड़ों की ओर लौट जाएंगे। वांगचुक का यह संदेश अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सामने आया है। सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में कहा कि मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाऊंगा और फिर पहाड़ों की ओर लौट जाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद और मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम के डॉक्टरों और स्टाफ की शानदार टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था। उन्होंने कहा था कि यह 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' और सड़कों से उठी जनता की आवाज की जीत है। उन्होंने शांति, धैर्य और दृढ़ता की सराहना करते हुए CJP, देश की जनरेशन Z और देशभर के नागरिकों को बधाई दी थी। इधर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट कर दावा किया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कुछ राज्यों में छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है और इन रिपोर्टों पर केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

(यूटीयू) प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रोफेसर डॉ. आशीष कुमार गुप्ता पर आजीवन प्रतिबंध

देहरादून, 27 जुलाई वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) ने सेमेस्टर परीक्षा के कथित प्रश्नपत्र लीक करने के आरोपी एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के गिरफ्तार सहायक प्रोफेसर डॉ. आशीष कुमार गुप्ता पर सभी शैक्षणिक कार्यों के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, सेमेस्टर परीक्षा 2025-26 के प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में संलिप्तता के आरोप के दृष्टिगत डॉ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से शिक्षण कार्य, पठन-पाठन, प्रश्नपत्र तैयार करने एवं सभी शैक्षणिक कार्य हेतु आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले, आरोपी सहायक प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा संबंधी कार्यों से आगामी सात वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया था तथा उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। देहरादून के 'शिवालिक कॉलेज आफ इंजीनियरिंग' ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि कथित प्रश्नपत्र लीक की इस घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसलिए विद्यार्थियों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। टीयू ने अपनी उच्चस्तरीय जांच में प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को सही पाए जाने के बाद पिछले सप्ताह इंजीनियरिंग के दो विषयों– मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट आफ थिंग्स और इलैक्ट्रोमेगनेटिक फील्ड थ्योरी की परीक्षाएं निरस्त कर दी थीं और उनकी पुनर्परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया था। आरोप है कि 'मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट आफ थिंग्स विषय का

प्रश्नपत्र बाहय पेपर सेटर के तौर पर डॉ गुप्ता ने तैयार किया था जिसके प्रश्न उन्होंने कथित तौर पर व्हाटसएप और आंतरिक पोर्टल पर कुछ छात्रों के साथ साझा कर दिए। लेकिन जांच समिति ने उनके द्वारा तैयार किए गए एक अन्य विषय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के प्रश्नपत्र में भी इसी प्रकार की विसंगति और गोपनीयता भंग होने की आशंका के मद्देनजर उसे निरस्त करने की सिफारिश की थी।

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला:

ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया बड़ी कानूनी गलती

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तय समय और लंबित मामलों की अधिकता के कारण वह आज इस मामले पर विस्तृत सुनवाई नहीं कर सकती। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील ने ईडी की याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों को दो महीने पहले ही जवाब दाखिल करने का समय दिया जा चुका था, लेकिन अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मेहता ने जोर देकर कहा कि यह पूरी तरह कानून की व्याख्या का मामला है और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष भविष्य के मामलों में भी बाधा बन सकते हैं।गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की मुख्य याचिका और ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं थी।ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा 'यंग इंडियन' को आरोपी बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि 'नेशनल हेराल्ड' प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अवैध तरीके से अधिग्रहण किया गया। ईडी के अनुसार, 'यंग इंडियन' ने 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया, जिसमें गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। मामला अब 10 सितंबर की सुनवाई पर केंद्रित है, जहां अदालत कानूनी पहलुओं पर विस्तृत बहस करेगी।

ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- गोला-बारूद की कोई कमी नहीं; अमेरिकी हथियार भंडार पर उठे सवाल

अमेरिकी हथियार भंडार घटने की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास जरूरत से कहीं अधिक गोला-बारूद मौजूद है।मीडिया रिपोर्टों में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी और सैन्य रणनीति पर उसके असर को लेकर चिंता जताई गई है।वहीं, ईरान ने साफ किया है कि वह दबाव में नहीं झुकेगा और शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समय) को उन बढ़ती चिंताओं को खारिज कर दिया कि सैन्य भंडार खतरनाक रूप से कम स्तर पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने उन खबरों का सीधे तौर पर खंडन किया जिनमें कहा गया था कि इंटरसेप्टर की कमी ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिकी सैन्य रणनीति को सीमित कर रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक बयान में, ट्रंप ने उन दावों को खारिज कर दिया कि गोला-बारूद की घटती मात्रा अमेरिकी रक्षा क्षमताओं के लिए कोई समस्या पैदा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारे पास दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक गोला-बारूद है, और हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति की ये बातें 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के जवाब में आई हैं। इस रिपोर्ट में प्रशासन के अंदर हुई बातचीत का ज़िक्र है, जिसमें जॉइंट चीफ्स ऑफ़ स्टाफ़ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने चिंता जताई थी कि अगर सैन्य कार्रवाई और बढ़ी, तो इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर का मानना है कि अमेरिकी सेना पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के सीमित स्टॉक को संभाल सकती है। इस रणनीति में अमेरिकी हमलों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है (जिसके लिए ट्रंप की मंज़ूरी का इंतज़ार है), ताकि ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर हमले शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। साथ ही, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से पैट्रियट और THAAD मिसाइलों के इस्तेमाल से जुड़े अमेरिकी सरकार के अपडेटेड आंकड़े जारी करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सटीक डेटा जारी करने में अधिकारियों की हिचकिचाहट के बावजूद, 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' के एनालिस्ट मार्क कैंसियन और क्रिस पार्क के अपडेटेड अनुमानों को उजागर किया है। उनके हिसाब से, संघर्ष शुरू होने के बाद से कम से कम 1,500 पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिससे अब अनुमानित तौर पर 1,000 से भी कम इंटरसेप्टर बचे हैं। ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि दो हफ्ते की भारी बमबारी के बावजूद वह दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हो रही बमबारी को रोक दी है, लेकिन तेहरान ने कहा- हम शांति वार्ता की भीख नहीं मांग रहे। इस बीच तेल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। ट्रंप ने हफ्ते के अंत में ईरान पर दो हफ्ते से चल रहे बमबारी अभियान को अचानक रोक दिया। उनके सैन्य सलाहकारों ने बताया कि अब लक्ष्य खत्म हो चुके हैं और हथियारों के स्टॉक भी कम हो रहे हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के जनरल डेन केन ने भी चिंता जताई कि क्षेत्र में अमेरिकी बेसों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहे एयर डिफेंस हथियार कम पड़ रहे हैं। उधर, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि यह रुकावट बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए है, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

फिलीपींस में न्याय मंत्रालय के बाहर जोरदार धमाका

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फिलीपींस से बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के संबोधन से ठीक पहले न्याय मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) के बाहर एक तेज विस्फोट हुआ। जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनी गई। यही नहीं धमाके के कुछ घंटे ही बाद सीनेट भवन के पास एक संदिग्ध 'इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (IED) भी मिला। स्थानीय पुलिस ने समय रहते दूसरे डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया। दोनों घटनाओं के बीच एक-दूसरे से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर जांच तेज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार आधी रात के बाद न्याय मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास एक घर में बना बम फट गया। राहत की बात यह रही कि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि पास में खड़ी एक गाड़ी चपेट में आ गई। उसका शीशा टूट गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। बता दें इसी दिन सुबह राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 5वें 'स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस' के जरिए देश को संबोधित करने वाले थे। इससे पहले सीनेट भवन के पास एक संदिग्ध IED मिलने से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गईं। बम निरोधक दस्ते ने डिवाइस को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के अनुसार, सीनेट के पास डायोको बुलेवार्ड पर एक टो ट्रक चालक ने संदिग्ध वस्तु देखकर सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी। इसके बाद बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान डिवाइस से ब्लास्टिंग कैप, 9V बैटरी, घड़ी और संदिग्ध विस्फोटक सामग्री वाला कंटेनर बरामद किया गया।

धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के साथ एनडीए सांसदों ने स्वागत किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर देशभर में चला कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ। यह आंदोलन NEET-UG पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और छात्रों की जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ था। करीब 35 दिन तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन चला। आंदोलन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे बड़ा मुद्दा बनी रही। लगातार बढ़ते दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच सोमवार यानी आज संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। संसद परिसर में भाजपा और NDA के कई सांसदों ने उनका जबरदस्त, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और "धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद" के नारे लगाए। इस्तीफे के बाद यह धर्मेंद्र प्रधान पहली सार्वजनिक मौजूदगी रही। संसद परिसर में भाजपा और NDA सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। इस दौरान "धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद" के नारे लगाए गए। कई सांसद उनके समर्थन में उनके साथ नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा CJP के छात्र आंदोलन के बाद आया था। उनके स्थान पर प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। CJP आंदोलन की मुख्य मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। आंदोलन NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ था। सरकार के मांगें मानने के बाद जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त हो गया।

भारतीय नाविकों पर हमलों को लेकर एंड्री सिबिहा ने एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने काला सागर में रूसी पोर्ट्स की ओर जाने और आने वाले विदेशी जहाजों के लिए खतरे को लेकर एक बयान जारी किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 2025-2026 में काला सागर में रूस के हमलों की वजह से नाविकों, समुद्री पायलटों और व्यापारी जहाजों के क्रू मेंबर्स सहित कई आम लोगों की मौत हुई। इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन के समुद्री एक्सपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। बयान के अनुसार, भारत में यूक्रेन के दूतावास ने कहा है कि उसका दृढ़ विश्वास है कि रूस की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण काला सागर और आजोव सागर में नागरिक जहाजों की आवाजाही पर मंडरा रहे खतरों और जोखिमों को क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति से जुड़ी किसी भी एहतियाती चेतावनी पर तत्काल प्रतिक्रिया देकर कम किया जा सकता है। दूतावास ने कहा कि युद्ध के दौरान यूक्रेन लगातार अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, जिनमें भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, को रूस की कार्रवाइयों से नागरिक नौवहन पर बढ़ते खतरों के बारे में आगाह करता रहा है।यूक्रेन ने अपने साझेदार देशों को उन कदमों की भी जानकारी दी है, जो वह सैन्य सामान की आपूर्ति रोकने और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समर्थन देने वाली लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के लिए उठा रहा है। दूतावास ने कहा कि इन चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के मंच पर भी औपचारिक रूप से उठाया गया है। इसके तहत 12 जून और 26 जून 2026 को जारी आईएमओ सर्कुलर लेटर्स के माध्यम से सदस्य देशों को अवगत कराया गया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसने भारत सरकार के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी सर्कुलर-41 का संज्ञान लिया है।

कनाडा में भारतीय मूल की युवती की गोली मारकर हत्या

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की 26 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि यह हमला संभवतः सोच-समझकर किया गया था। हत्या के आरोप में भारतीय मूल के ही एक 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। टोरंटो पुलिस सर्विस ने शनिवार को एक बयान में बताया कि गोलीबारी की घटना शुक्रवार सुबह हम्बरवुड बुलेवार्ड और रेक्सडेल बुलेवार्ड (सड़क का नाम) के चौराहे पर हुई। मृतक महिला की पहचान नवनीत कौर के तौर पर हुई, जबकि ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान ब्रैम्पटन के शरणजीत सिंह के तौर पर हुई।पुलिस ने कहा कि सुबह करीब 7:23 बजे गोलीबारी की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और कौर को गोली लगी हुई हालत में पाया। जान बचाने की कोशिशों के बावजूद, उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि सुबह करीब 7:23 बजे गोलीबारी की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और कौर को गोली लगी हुई हालत में पाया। जान बचाने की

कोशिशों के बावजूद, उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी शरणजीत सिंह पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर और अंडरटेकिंग (कानूनी वचन) का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह घटना सोच-समझकर की गई थी और अब कोई अन्य संदिग्ध नहीं है। होमिसाइड यूनिट (हत्या की जांच करने वाली इकाई) मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक गवाह ने पुलिस को बताया कि कौर हम्बरवुड बुलेवार्ड पर चल रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, थोड़ी देर बात की और फिर एक बार गोली मारकर पैदल ही भाग गया। महिला को गिरते हुए देखकर गवाह ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन किया।यह घटना इस महीने की शुरुआत में अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन में भारतीय मूल की एक अन्य महिला की उसके साथी द्वारा हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। पिछले हफ्ते, 22 वर्षीय रितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उस पर सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। उस पर अपनी 23 वर्षीय साथी दमनप्रीत कौर का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इसे 'इंटिमेट पार्टनर होमिसाइड' (साथी द्वारा की गई हत्या) बताया है।

संपादक की कलम से

शिक्षा से राजनीति तक—जवाबदेही की असली परीक्षा :

देश की राजनीति इन दिनों कई ऐसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों, खासकर युवाओं और छात्रों से है। चाहे ओडिशा की स्कूली किताबों में गंभीर त्रुटियों का मामला हो, बिहार में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन, या फिर दलबदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी—इन सभी घटनाओं के केंद्र में एक ही सवाल है: क्या लोकतंत्र में जवाबदेही केवल विपक्ष का मुद्दा है, या सरकार और संस्थाओं की भी समान जिम्मेदारी है?ओडिशा में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में तथ्यात्मक और भाषाई गलतियों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किताबें किसी भी समाज की अगली पीढ़ी का बौद्धिक आधार होती हैं। यदि उनमें इतिहास, भाषा या तथ्यों से जुड़ी गलतियां हों, तो इसका असर केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों की सोच और समझ पर भी पड़ता है। ऐसे मामलों में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह केवल त्रुटियों को सुधारने तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।दूसरी ओर, बिहार में NEET पेपर लीक के विरोध में हुए आंदोलन ने युवाओं के भीतर बढ़ते असंतोष को सामने ला दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर लगातार उठते सवाल लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि विश्वास के संकट का संकेत भी है। ऐसे समय में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल व्यवस्था बनाए रखने की नहीं, बल्कि छात्रों के भरोसे को भी कायम रखने की होती है।इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दलबदल विरोधी कानून को लेकर दाखिल याचिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक और कमजोरी उजागर की है। यदि राजनीतिक दलों के विलय या विभाजन की आड़ में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के जनादेश को बदल सकते हैं, तो लोकतंत्र की मूल भावना प्रभावित होती है। अदालत ने भी संकेत दिया है कि इस कानून में व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिन पर संसद और राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन घटनाओं का साझा संदेश स्पष्ट है—संस्थाओं की विश्वसनीयता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, परीक्षाओं की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आती है या जनादेश की पवित्रता पर बहस होती है, तब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलता। समाधान पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सुधारों में ही निहित है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होगी कि सरकारें आलोचना को अवसर मानती हैं या विरोध समझकर टाल देती हैं।

ओडिशा में किताबों की गलतियों पर सियासी संग्राम
नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की उठाई मांग

ओडिशा की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सामने आई तथ्यात्मक, भाषाई और मुद्रण संबंधी गलतियों को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है।नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने इस मामले में शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है।बीजू जनता दल का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों तक गलत जानकारी पहुंची है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ओडिशा में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सामने आई गंभीर त्रुटियों को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने इस पूरे मामले में स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर शिक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब बच्चों की शिक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय में बार-बार गंभीर गलतियां सामने आ रही हैं, तो इसकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए।नवीन पटनायक ने कहा कि पिछले कुछ समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कई पाठ्यपुस्तकों में तथ्यात्मक, भाषाई और व्याकरण संबंधी गलतियां सामने आई हैं। उनका कहना है कि पाठ्यपुस्तकें केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि बच्चों के ज्ञान और भविष्य की बुनियाद होती हैं। यदि इनमें गलत जानकारी प्रकाशित होगी तो छात्रों के मन में भ्रम पैदा होगा और उनकी पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है और इस तरह की लापरवाही को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।बीजू जनता दल प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण अपनाते हुए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी पिछले दो से तीन सप्ताह से लगातार इस मुद्दे को विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर उठा रही है, लेकिन सरकार अब तक प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।दरअसल, हाल ही में ओडिशा की कई स्कूली किताबों में वर्तनी, व्याकरण और मुद्रण संबंधी अनेक त्रुटियां सामने आई थीं। इतना ही नहीं, कुछ अध्यायों में ऐतिहासिक तथ्यों और महत्वपूर्ण जानकारियों को भी गलत तरीके से प्रकाशित किए जाने के आरोप लगे। कई स्थानों पर शब्दों और वाक्यों की छपाई में भी गंभीर खामियां पाई गईं, जिससे छात्रों और शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन त्रुटियों के सामने आने के बाद अभिभावकों और शिक्षकों ने भी चिंता जताई और मांग की कि बच्चों को केवल प्रमाणिक और त्रुटिरहित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।इस पूरे मामले को लेकर बीजू जनता दल लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने पुस्तकों के प्रकाशन से पहले उनकी पर्याप्त जांच नहीं कराई, जिसके कारण बड़ी संख्या में गलतियां सीधे छात्रों तक पहुंच गईं। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इन त्रुटियों को स्वीकार करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और संशोधित संस्करण उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि केवल सुधार का आश्वासन पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यह विवाद ओडिशा की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।

इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

इस्तीफे के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला रिएक्शन आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो एसी रूम में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं। दरअसल, संसद भवन के कॉरिडोर में धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच मुलाकात हुई थी। पुराने दिन को याद करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जयराम रमेश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नेंस की तारीफ की थी और मैं इन्हें ढूंढते हुए AICC दफ्तर चला गया था। फिर ये कॉमर्स मिनिस्टर बने और मैं सांसद बना मैं इनके ऑफिस में अपने इलाके की मिर्ची के मुद्दे पर मिला मिला था। इस बीच जयराम ने कहा इट हैपन्स, जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही।धर्मेंद्र प्रधान ने जयराम रमेश को रिप्लाई करते हुए कहा, "नथिंग हैपन्स आई एम ए स्ट्रीट फाइटर, नोट ए एसी रूम एक्टिविस्ट।" इससे पहले सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया गया। आपको 2 साल पुराने 2024 के कानून और नया कानून में अंतर बताते हैं।एंटी पेपर लीक कानून में अलग वर्ग के लिए अलग प्रावधान हैं, जैसे कोई अकेला शख्स दोषी है तो उसके लिए अलग प्रावधान हैं। अगर कोई संगठित गिरोह का सदस्य है तो उसके लिए अलग प्रावधान हैं। एंटी पेपर लीक में सिर्फ संगठित गिरोह के मेंबर्स के लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि सर्विस प्रोवाइडर फर्म यानि जो बॉयोमैट्रिक और प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्ट में शामिल एजेंसियां हैं अगर उसके सदस्य या डायरेक्टर या प्रबंधन के सीनियर मैनेजर या कोई और दोषी पाया जाता है तो उसे पहले 5 साल तक की सजा मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। साथ ही जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ दी गई है। वहीं, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज जब सोमवार को पहली बार संसद भवन पहुंचे तो NDA सांसदों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर मुस्कान थी। इस पर एक सांसद ने कहा पहली बार है जब किसी मंत्री ने बिना किसी आरोप के ही इस्तीफा दे दिया।

दलबदल कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
विलय के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को एक PIL पर नोटिस जारी किया। यह PIL कपिल सिब्बल ने दायर की थी, जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी गई है जो विधायकों को राजनीतिक पार्टी के विलय के ज़रिए दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य होने से बचने की इजाज़त देती है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारत के दलबदल विरोधी कानून से जुड़ी "बड़ी समस्याओं" का ज़िक्र करते हुए बेंच ने कहा कि यह कानून विधायिका ने बनाया है।बेंच ने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता, तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए।10वीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज के तरीके को रेगुलेट करना है। हमने देखा है कि 10वीं अनुसूची के कामकाज में कई बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? इसे संसद सदस्यों (MP) ने ही बनाया है। सिब्बल ने जवाब दिया कि कभी-कभी सांसद भी गलतियाँ कर सकते हैं और हो सकता है कि यह मामला कभी सुलझ ही न पाए क्योंकि इससे सत्ता में बैठे लोगों को फायदा होता है। सिब्बल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग कभी भी इस मामले का फैसला नहीं होने देंगे। सिब्बल, जो एक सांसद भी हैं, ने कहा, कृपया इस प्रस्ताव पर गौर करें। समस्या की गंभीरता को समझें। चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है। एक अल्पसंख्यक समूह बहुमत में बदल सकता है और बहुमत वाला समूह अल्पसंख्यक बन सकता है। सिब्बल ने दसवीं अनुसूची के तहत विलय से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिक व्याख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्याख्या के कारण अलग हुए गुट, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ विलय करके दलबदल विरोधी कानून की सख्ती से बच सकते हैं।

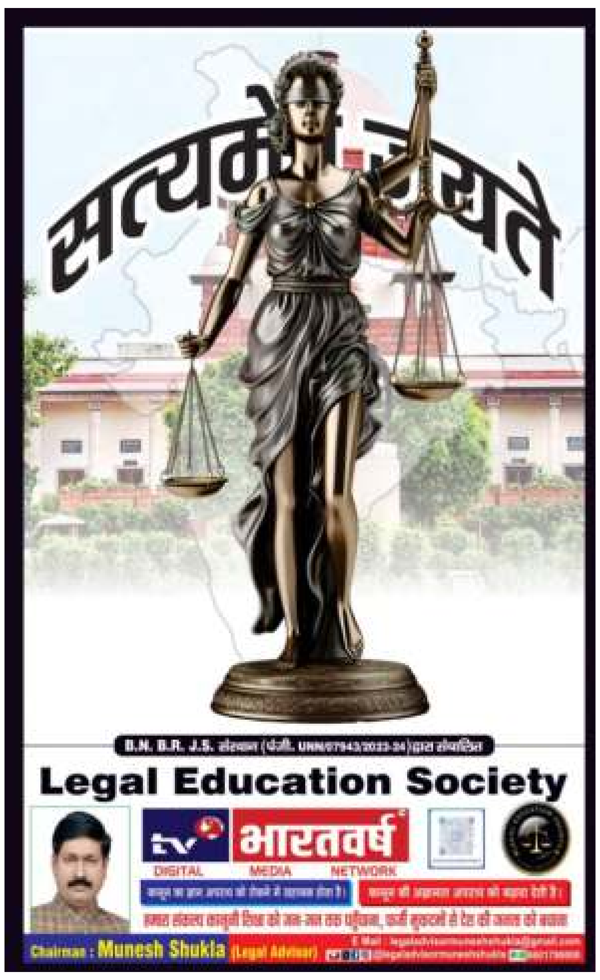

अग्निवीर भर्ती रैली में भूलकर भी न करें ये गलतियां भारतीय सेना ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए देशभर में अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जा रही हैं। अलग-अलग जोन में चल रही इन रैलियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण उम्मीदवार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका चयन प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में फर्जी या जाली दस्तावेज लेकर न आएं। सभी आवश्यक प्रमाणपत्र और पहचान पत्र पूरी तरह सही और वैध होने चाहिए। यदि किसी दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।इसके अलावा सेना ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए केवल भर्ती कार्यालय के अधिकृत अधिकारियों से ही संपर्क करें। किसी दलाल, एजेंट या अन्य व्यक्ति के बहकावे में न आएं। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर चयन कराने का दावा करता है तो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें, क्योंकि सेना में भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर होती है।स्वास्थ्य को लेकर भी सेना ने महत्वपूर्ण सलाह दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को हाल ही में गंभीर चोट लगी है या वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तो उसे रैली में शामिल होने से बचना चाहिए। शारीरिक परीक्षण के दौरान ऐसी स्थिति चयन में बाधा बन सकती है।सेना ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार अपने जिले और ट्रेड के लिए निर्धारित तिथि पर ही रैली स्थल पर पहुंचें। अनावश्यक भीड़ से बचने और भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए समय का पालन करना जरूरी है। साथ ही रैली में महंगे मोबाइल फोन, आभूषण या अन्य कीमती सामान लेकर न आने की सलाह दी गई है।रैली के दौरान अनुशासन बनाए रखना भी अनिवार्य है। अन्य उम्मीदवारों या भर्ती स्टाफ के साथ किसी प्रकार का विवाद, बहस या झगड़ा न करें। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि से दूर रहें।सेना ने यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया रैली के बाद भी जारी रहती है। मेडिकल समीक्षा के लिए निर्धारित सैन्य अस्पताल में समय पर पहुंचना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) में उपस्थित होना और प्रशिक्षण के लिए तय तिथि पर रिपोर्ट करना प्रत्येक उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। किसी भी चरण में अनुपस्थित रहने या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह भेजने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।भारतीय सेना ने अंत में दोहराया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर चयन कराने या विशेष मदद का दावा करता है, तो उससे तुरंत दूरी बनाएं और उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

इस साल कैट एग्जाम 29 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा, लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन कैट एप्लीकेशन फॉर्म 03 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से भरा जाएगा और परीक्षा नवंबर 2026 में होगी। उम्मीदवार आईआईएम कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। C A T एक नेशनल-लेवल की एंट्रेंस परीक्षा है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) द्वारा कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के जरिए 21 IIMs और कई दूसरे बड़े बिजनेस स्कूलों में एडमिशन मिलता है। हर साल करीब तीन लाख उम्मीदवार कैट एग्जाम में बैठते हैं।CAT एग्जाम कौन दे सकता है?
CAT 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कम से कम 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए।
SC, ST और PwD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 45% मार्क्स जरूरी हैं।
अंडरग्रेजुएट कोर्स के आखिरी साल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
परीक्षा के लिए उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
How to Apply for CAT 2026 : यहां देखें आवेदन का तरीका
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
होमपेज पर 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें।
अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक रिकॉर्ड समेत जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
एप्लीकेशन फीस जमा करें।
फॉर्म जमा करें और आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले लें।

भारत अब भी बना सकता है WTC के फाइनल में जगह

सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की वापसी की तैयारी शुरू कर दी

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2026 का आईसीसी टी20 विश्व कप जीता था, लेकिन इसके बाद न केवल उनकी कप्तानी ले ली गई, बल्कि टीम से भी बाहर हो गए। हालांकि सूर्या ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बार फिर से वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच सूर्या ने रविवार को खूब पसीना बहाया और रात करीब एक बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ दिनों से गुमनामी के अंधेरे में थे, लेकिन इस बीच रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात 12 बजकर 57 मिनट पर सूर्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि रविवार का दिन मजेदार रहा। जल्दी जल्दी दौड़ा और तीन घंटे में लगभग 1000 बॉल खेलीं। इससे अच्छा लगा। साथ ही सूर्या ने अपनी तैयारी का वीडियो भी शेयर किया है। इससे पता चलता है कि सूर्या ने टीम इंडिया में वापसी की अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी है। टीम इंडिया ने भले ही साल 2026 का विश्व कप सूर्या की कप्तानी में जीता हो, लेकिन इस बीच उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं बने। विश्व कप के बाद जब सूर्या आईपीएल में अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के लिए उतरे तो वहां भी उनके बल्ले से रन नहीं बने। इसका खामियाजा उन्हें टीम से अपनी जगह गवां कर भुगतना पड़ा। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान बनाया गया। हालांकि श्रेयस की शुरूआत काफी खराब रही। पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड से सीरीज हारी। इसके बाद इंग्लैंड से भी सीरीज हार गई। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। हालांकि अब श्रेयस की गाड़ी पटरी पर लौट आई है। उनकी कप्तानी में टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीत ली है। जब सूर्यकुमार यादव खेल रहे थे, तब भी वे केवल एक ही फॉर्मेट में नजर आते थे।

भारत की ईशा सिंह ने 40 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता

भारत की उदीयमान निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को यहां I S S F विश्व कप (राइफल/पिस्तौल/शॉटगन) में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक पदक विजेता हमवतन खिलाड़ी मनु भाकर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। भाकर ने कांस्य पदक जीता और भारत ने इस तरह से इस स्पर्धा में दो पदक हासिल किए। 21 साल की ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 अंक बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि पेरिस 2024 ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु ने शूट-ऑफ जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 28 अंक बनाए। भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालीफाइंग दौर से ही अच्छी शुरुआत की। मनु ने 586 अंक बनाकर क्वालीफाइंग में पहला स्थान हासिल किया जबकि ईशा 585 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही। इस तरह से इन दोनों ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में आसानी से जगह बनाई। एशियाई खेलों की पूर्व गोल्ड मेडल विजेता राही सरनोबत ने 582 का स्कोर बनाया, जबकि सिमरनप्रीत कौर बराड़ और अभिदन्या अशोक पाटिल ने केवल रैंकिंग अंकों के लिए (आरपीओ) खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। ईशा और मनु की जीत के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने दोनों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी। इस सत्र के शुरू में म्यूनिख विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा ने कहा, 'पिछली जीत के कारण मुझ पर काफी दबाव था। जब आप अपनी स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपसे काफी उम्मीद की जाती है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत को और पदकों की उम्मीद

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पांचवे दिन के एवेंट्स चल रहे हैं। पहले चार दिनों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के 17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 39 मेडल हैं और वह टैली के टॉप पर है। भारत ने एक गोल्ड दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 48 किलोग्राम भारवर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मेन्स 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। वहीं मुथुपांडी राजा मेंस 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में 286 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। वहीं झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की एथलेटिक्स टीम की अगुआई ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। गोल्ड कोस्ट 2018 में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज इस बार भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक तालिका में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। चोट के कारण वह बर्मिंघम 2022 में अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके थे, ऐसे में इस बार उनकी नजर दोबारा स्वर्ण पदक जीतने पर होगी। पांचवे सीन भारतीय खिलाड़ी ट्रैक और फील्ड मुकाबले में उतरेंगे। स्कॉट्सन स्टेडियम में पुरुषों की 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 110 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद के साथ एथलेटिक्स इवेंट्स शुरू होंगे। वहीं, भारत के वेटलिफ्टर रविवार को ऋषिकंता सिंह और मीराबाई चानू द्वारा जीते गए सिल्वर और गोल्ड मेडल में और मेडल जोड़ने की कोशिश करेंगे। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम (महिलाओं का 58 किग्रा),

अजय बाबू (पुरुषों का 79 किग्रा) और ज्ञानेश्वरी यादव (महिलाओं का 53 किग्रा) शामिल होंगे। पैरा एथलीट भी एक्शन में होंगे, जिसमें पुरुषों की T38 100 मीटर दौड़ और महिलाओं का शॉट पुट F57 इवेंट होगा। साथ ही, भारत के पांच बॉक्सर भी मुकाबले में उतरेंगे।

500 करोड़ में बिक रहा एक फ्लैट

एक, दो करोड़ के आलीशान फ्लैट्स के बारे में तो आपने काफी सुना होगा. इन दिनों चर्चा एक ऐसे फ्लैट की है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है. एक फ्लैट की कीमत 500 करोड़ रुपये देख हर कोई हैरान है कि आखिर इस फ्लैट में ऐसा क्या होगा. वैसे ये फ्लैट भारत में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क शहर में बिक रहा है. लेकिन, वहां के लोग भी फ्लैट के इतने रेट देखकर हैरान हैं. बता दें कि न्यूयॉर्क में फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में काफी लग्जरी फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें एक अपार्टमेंट की कीमत 58.5 मिलियन डॉलर तक है यानी भारत के 500 करोड़ रुपये. ये फ्लैटिरॉन बिल्डिंग एक खास ट्राइएंगल शेप की है, जो काफी डिजाइनर भी है. वैसे ये आज से नहीं, बल्कि कई सालों से न्यूयॉर्क शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक रहा है और आज भी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है.

भारत के Gen-Z ने विरोध की भाषा बदली

एम. नूरुद्दीन, आजतक

अगर दस साल पहले कोई कहता कि एक दिन मीम बनाने वाली पीढ़ी किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लेगी, तो शायद लोग हंस देते. मतलब सालों तक एक बात बार-बार दोहराई जाती रही कि आज की Gen-Z सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित है. कहा जाता था कि यह पीढ़ी मीम बनाती है, रील्स देखती है, राजनीति से दूर रहती है और किसी बड़े सामाजिक मुद्दे के लिए सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं रखती. लेकिन दक्षिण एशिया की पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत तक युवाओं ने अपने-अपने मुद्दों पर सत्ता से सवाल पूछे. कहीं सरकारें गिर गईं, कहीं प्रधानमंत्री बदल गए और कहीं पूरी राजनीतिक व्यवस्था हिल गई. लेकिन इन सब आंदोलनों के बीच अगर किसी एक आंदोलन ने यह दिखाया कि लोकतंत्र में विरोध सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि संयम, व्यंग्य और संवाद से भी जीता जा सकता है, तो वह भारत का Gen-Z आंदोलन था. नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही घंटों में हिंसक टकराव में बदल गया था. बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण विवाद देखते-देखते सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गया. प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा. श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति भवन तक भीड़ पहुंच गई.

अमेरिका में रहने वाले लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढना हुआ मुश्किल

NRI दूल्हों से दूरी क्यों बना रहीं लड़कियां?

कभी NRI दूल्हे से शादी को बेहतर भविष्य की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. अमेरिका समेत कई देशों में बसे NRI युवकों के रिश्तों में गिरावट की चर्चा के बीच Reddit पर हुई बहस ने बताया कि भारतीय महिलाओं की प्राथमिकताएं क्यों बदल रही हैं.

एक समय था जब NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) दूल्हे से शादी करना कई भारतीय परिवारों का सपना माना जाता था. विदेश में नौकरी, बेहतर कमाई और स्थायी जीवन की उम्मीद की वजह से ऐसे रिश्तों को प्राथमिकता दी जाती थी.

लेकिन अब यह ट्रेंड धीरे-धीरे बदलता दिख रहा है. हाल के सालों में खासकर अमेरिका में रहने वाले NRI युवकों के लिए भारत में रिश्ते ढूंढना पहले जितना आसान नहीं रहा. इसकी वजह सिर्फ वीजा नियम नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं और उनके परिवारों की बदलती सोच भी मानी जा रही है.

VisaVerge की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाले NRI युवकों के रिश्तों में रुचि करीब 25 फीसदी तक घटी है. रिपोर्ट के अनुसार, इसके पीछे सख्त इमिग्रेशन नियम, वीजा से जुड़ी अनिश्चितताएं, जीवनसाथी के काम करने के अधिकार और विदेश में लंबे समय तक बसने को लेकर बढ़ती चिंताएं प्रमुख कारण हैं. इसी मुद्दे पर रेडिट पर एक यूजर ने सवाल पूछा कि क्या अब NRI लड़कों के लिए भारत में शादी का रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो गया है?यूजर ने लिखा कि उनके आसपास कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अच्छी नौकरी और स्थिर करियर होने के बावजूद NRI युवकों को सिर्फ कुछ धारणाओं की वजह से मना कर दिया गया.

महिलाओं ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर कई महिलाओं और अन्य रेडिट यूजर्स ने अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा कि यदि कोई महिला भारत में अच्छी नौकरी कर रही है, तो वह सिर्फ शादी के लिए अपना करियर छोड़कर विदेश क्यों जाए, खासकर तब जब वहां नौकरी मिलने की कोई गारंटी न हो. एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत में नौकरी करते हुए घरेलू मदद मिल जाती है, जबकि विदेश में नौकरी न मिलने की स्थिति में महिला को घर के काम भी संभालने पड़ सकते हैं और सामाजिक दायरा भी सीमित हो सकता है.

युवक ने बताया यूरोप की 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' का सीक्रेट

क्या किसी शहर की अच्छी जिंदगी सिर्फ ऊंची सैलरी, बेहतरीन हेल्थकेयर और आधुनिक तकनीक से तय होती है? जर्मनी में रहने वाले एक भारतीय युवक का मानना है कि इसका जवाब 'नहीं' है. उनका कहना है कि यूरोप की असली ताकत उसकी लोगों को केंद्र में रखकर की गई शहरी प्लानिंग है. इस मुद्दे पर बनाया गया उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं.

'रामायण' में रावण बनना सबसे बड़ी चुनौती:

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में बोले यश, ट्रेलर रिलीज टली

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान अमेरिका में शुरू हो चुका है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के मंच पर फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स एक खास पैनल चर्चा और इंटरव्यू के लिए एक साथ नजर आए। इस ग्रैंड इवेंट के दौरान फिल्म में 'रावण' की मुख्य भूमिका निभा रहे साउथ सुपरस्टार यश ने इस ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र को पर्दे पर जीवंत करने के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस बहुचर्चित किरदार को निभाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रहा है।कॉमिक-कॉन से अलग IGN के साथ एक बातचीत में यश ने अपने सह-कलाकार रणबीर कपूर, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ हिस्सा लिया। बचपन की यादों को साझा करते हुए यश ने कहा कि रामायण संभवतः पहली ऐसी कहानी थी जो उन्होंने अपने दादाजी से सुनी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि चूंकि लोगों के मन में रावण की एक खास छवि पहले से बसी हुई है, इसलिए इस किरदार को निभाते समय उन पर एक अलग तरह का दबाव था। यश ने बताया, 'यदि आप किसी नई कहानी पर काम कर रहे हों तो आप जो भी अभिनय करते हैं वही चरित्र की पहचान बन जाता है। लेकिन रावण जैसे जगजाहिर किरदार के लिए, जिसे कई महान कलाकार पहले ही अलग-अलग अंदाज में निभा चुके हैं, काम करना काफी कठिन होता है। फिर भी मैंने बहुत बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया और यह समझने की कोशिश की कि उसने वे फैसले क्यों लिए। निर्देशक और लेखकों ने मुझे यह आजादी दी कि मैं इस चरित्र में अपना एक नया दृष्टिकोण ला सकूं।' रामायण दुनिया के सबसे प्राचीन और आदरणीय महाकाव्यों में से एक है, जिसे भारतीय सिनेमा और टीवी पर सैकड़ों बार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय दर्शकों के दिलों में स्क्रीन पर रावण के कुछ चित्रण हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। इनमें 1960 के दशक में तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एन. टी. रामाराव और 1988 के ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक में महान अभिनेता अरविंद त्रिवेदी द्वारा निभाई गई रावण की भूमिकाएं सबसे प्रमुख हैं। ऐसे में यश के लिए इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। कॉमिक-कॉन में फैंस को उम्मीद थी कि इस इवेंट का समापन फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के साथ होगा। हालांकि ऐन वक्त पर फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेलर की रिलीज को फिलहाल के लिए टालने की घोषणा की। नमित ने बताया कि 'रामायण' को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने 'सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट' के साथ अंतरराष्ट्रीय वितरण का एक बड़ा सौदा किया है। इसी रणनीतिक साझेदारी के कारण अब फिल्म का ट्रेलर बाद में एक नए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। इसी इवेंट में रणबीर कपूर ने भी बताया कि उन्होंने राम बनने की तैयारी कैसे की। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो भागों में बनने वाली एक भव्य फ्रेंचाइजी है। इसका पहला भाग इसी साल नवंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि साईं पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। इनके अलावा फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर जैसे कई दिग्गज कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

परीक्षा संशोधन विधेयक से पहले अखिलेश का सरकार पर हमला बोले- युवाओं की जागरूकता को चुनौती देना बंद करे सरकार

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है।

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और युवाओं की जागरूकता को चुनौती देने के बजाय उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार लगातार छात्रों के आंदोलनों को दबाने और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है, जबकि युवाओं की आवाज लोकतंत्र की ताकत होती है।संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देशभर में छात्र और युवा अपने भविष्य, परीक्षाओं की पारदर्शिता और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मांगों का समाधान निकालने के बजाय आंदोलन कर रहे युवाओं पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार को युवाओं और छात्रों की जागरूकता को चुनौती नहीं देनी चाहिए। अब यही जागरूकता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।"अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा का मुद्दा केवल किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उनका कहना था कि छात्रों का संघर्ष केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बहाल करने की लड़ाई भी है।समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के बाद से देश की शिक्षा प्रणाली लगातार संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने छात्रों के धैर्य और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उनकी आवाज को दबाने में सफल नहीं होगी।परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में परीक्षा प्रणाली में सुधार चाहती थी तो यह कदम 2014 में ही उठाया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, समय रहते सुधार किए गए होते तो आज देश को बार-बार पेपर लीक और परीक्षा विवादों का सामना नहीं करना पड़ता।वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा कि उनकी पार्टी अब तक जिस राजनीतिक रास्ते पर चलती आई है, उसी दिशा में आगे भी बढ़ेगी और किसी से अनावश्यक टकराव की जरूरत नहीं है।गौरतलब है कि केंद्र सरकार लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक, नकल और अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर अधिक सख्ती से रोक लगाना, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाना है। विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ-साथ सरकार को शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाओं पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए।

जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के विरोध में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने सोमवार को लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ दारूलशफा से विधानसभा तक पैदल मार्च शुरू किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके थोड़ी दूरी पर ही उन्हें रोक लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ पुलिस बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक दारूलशफा से विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। आरएलडी कार्यालय के बाहर पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई दंडात्मक है और इसका सबसे बड़ा नुकसान वहां पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण से जुड़े सभी निर्देश तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर इस तरह की कार्रवाई से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है और शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे वहां अध्ययनरत छात्रों का भविष्य भी दांव पर लग गया है।

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद, परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 21 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 32679 पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस बार लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून, 2026 को राज्यभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे जो कुल 300 अंकों के थे। मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की थी जिसमें हर गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे जाएंगे। बोर्ड ने 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी करके उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं। पिछली भर्तियों के कटऑफ के रुझानों को देखें तो इस बार भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े रिजल्ट के साथ आएंगे लेकिन संभावित रूप से जनरल वर्ग का कटऑफ 214.04, EWS वर्ग का 187.31, OBC कैटेगरी का 198.99, SC का 178.04 और ST का कटऑफ 146.73 के आसपास रहने की उम्मीद है। कटऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही भर्ती के अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 32679 पदों पर होने वाली इस भर्ती में सभी

वर्गों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 13093 पद, EWS के लिए 3264 पद, OBC के लिए 8818 पद, SC के लिए 6857 पद और ST वर्ग के लिए कुल 647 पद तय किए गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा का कटऑफ पार कर लेंगे उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहां उम्मीदवारों के शैक्षणिक और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा। इसमें सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों की लंबाई 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना जरूरी है।

लखनऊ में पंचायत सचिव ने तगड़ा कांड कर दिया वीडियो आया सामने

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

पंचायत बेव सीरीज के सचिव जी तो आपको याद होंगे..। लेकिन लखनऊ में पंचायत सचिव ने तगड़ा कांड कर दिया। मामला माल विकास खंड का है। यहां तैनात पंचायत सचिव सदगुरू प्रसाद का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह किसी पार्टी में डांसर के साथ स्टेज पर झूम रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में 'जिंदगी इम्तिहान लेती है और लोगों की जान लेती है...' गाना बज रहा है। जिस पर पंचायत सचिव हंस रहे और बहके-बहके नजर आ रहे। गांव वालों का कहना है कि सचिव साहब शराब पीकर डांस कर रहे थे। किसी सरकारी कर्मचारी को इस तरह इलाके में माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। वहीं दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने वीडियो को लेकर पंचायत सचिव सदगुरू से टेलीफोन पर बातचीत की। इस पर उन्होंने कहा कि वीडियो पुराना है, लोग इसे तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सदगुरू प्रसाद पिछले 3 सालों से माल विकास खंड में तैनात हैं। उनके पास नबीपनाह, आंट, सैदापुर और हसनापुर ग्राम पंचायतों का प्रभार है। इससे पहले सद्गुरु प्रसाद 7 साल तक मलिहाबाद में तैनात रहे। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ग्रामीणों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि पंचायत सचिव निजी कार्यक्रमों में अक्सर डांस करते नजर आते हैं। सचिव काफी समय से इसी विकासखंड में तैनात हैं। ऐसे में उनके काम की भी जांच कराई जानी चाहिए।

लखनऊ में सोमवार से मानसून फिर एक्टिव बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में आज सोमवार से फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान बादलों का गरज-चमक भी जारी रहेगा। सोमवार सुबह से शहर में बादल छाए हुए हैं। गोमतीनगर, समता मूलक चौराहा समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में रुक-रुककर बरसात होती रहेगी। इससे उमसभरी गर्मी से राहत मिलेगी। शहर में अभी तक सामान्य से 36 फीसदी कम बरसात हुई है। अब तक करीब 196 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.2 अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 92 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 56 फीसदी रही। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में भी बरसात का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत इसके आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है।

लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ प्रदर्शन छात्रों नेनेताओं के खिलाफ शर्म करो-शर्म करो के नारे लगाए

लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उनके साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन नेताओं के खिलाफ शर्म करो-शर्म करो के नारे लगाए। उनका कहना था कि जहां भी गैर-एनडीए सरकारें हैं, उन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही लोग जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दे रहे थे। इन नेताओं को अपनी पार्टी या गठबंधन के शिक्षामंत्रियों से इस्तीफा मांगना चाहिए। छात्र प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के गेट से सड़क पर निकलने लगे तो पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें पकड़ते हुए विश्वविद्यालय अंदर ही रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने बैरिकेडिंग भी धकेल दी। छात्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर-1 (आजाद द्वार) पर दोपहर 12 बजे इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे थे। छात्र

गेट के पास पहुंचकर विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलने पर अड़ गए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। छात्र आलोक मिश्रा ने कहा कि आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय से यह मांग करते हैं कि जहां भी गैर-एनडीए सरकारें हैं, उन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। वहां के शिक्षामंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां के शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दें। छात्र जतिन शुक्ला ने कहा कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें राज्यों के लिए भी बोलना चाहिए। झारखंड, कर्नाटक, केरल में पेपर लीक हुआ तो वहां के लिए भी इन्हें आवाज उठानी चाहिए।

उद्घाटन के 12 दिन बाद धंसा ₹4700 करोड़ का कानपुर-लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, सपा ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले में हुई बारिश के बाद ₹4700 करोड़ की लागत से बने कानपुर-लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा उद्घाटन के महज 12 दिन बाद धंस जाने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार और निर्माण एजेंसी पर निशाना साधा है। वहीं, निर्माण एजेंसी ने प्रभावित हिस्से की तत्काल मरम्मत कर सड़क को दुरुस्त करने का दावा किया है।जानकारी के मुताबिक, कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में उन्नाव के कोरारी क्षेत्र के पास भारी बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी बैठ गई, जिससे सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने के कारण उस स्थान पर पानी भर गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद निर्माण एजेंसी ने मौके पर पहुंचकर पैचवर्क के जरिए क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर दी, ताकि यातायात सामान्य रूप से जारी रह सके।गौरतलब है कि इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया था। इसे कानपुर और लखनऊ के बीच तेज और सुगम यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है।घटना के बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के हजारों करोड़ रुपये से बने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के कुछ ही दिनों बाद उसका धंस जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सपा ने अपने पोस्ट में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परियोजना में कथित कमीशनखोरी की भी बात कही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सरकार से जवाब मांगा।वहीं, इस मामले पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नई बनी सड़कों पर बारिश के दौरान इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं कभी-कभी सामने आ जाती हैं। उनका कहना था कि जहां भी सड़क में खराबी होगी, वहां तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह छोटी-छोटी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल, सड़क की मरम्मत कर यातायात बहाल कर दिया गया है। हालांकि, घटना के बाद एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित विभाग इस मामले की तकनीकी जांच कराता है या नहीं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

3.85 करोड़ का गड़बड़झाला, डीएम करा रहे हैं पिछले चार साल की जांच

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जिम्मेदारों की कमाई का जरिया बन गई हैं। तीन साल पहले हुए 3.85 करोड़ के घपले में 24 जुलाई को तत्कालीन प्रभारी के निलंबन करने के बाद मामले ने फिर तूल पकड़ा है। विभाग में यह गड़बड़झाला नया नहीं है। पुरवा में दो माह पूर्व 11 लाख रुपये बीएमएम द्वारा गबन किए जाने का मामला पकड़ा जा चुका है। इसको देखते हुए डीएम पिछले चार साल में समूहों को मिले करीब 50 करोड़ की जांच करा रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनआरएलएम योजना में हुए 3.85 करोड़ के घपले में तीन दिन पहले तत्कालीन प्रभारी संजय पांडेय को निलंबित किया गया था। एनआरएलएम में वर्तमान में पुरवा में एक गड़बड़झाले की जांच चल रही है। पुरवा में जनसुनवाई पोर्टल पर फर्जी समूह गठित करके सरकारी धन हड़पने की आई शिकायत पर डीएम ने जांच टीम गठित की थी।टीम में उपायुक्त स्वत: रोजगार भानु प्रताप सिंह, जिला मिशन प्रबंधक प्रदीप कुमार, अशोक कुमार व रजीउल हसन ने पुरवा विकासखंड आकर जांच की थी। बैंक स्टेटमेंट, अन्य अभिलेखों के साथ स्थलीय सत्यापन में जानकारी हुई थी कि ब्लाक में बीएमएम दीपराज ने तीन महिला समूह कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित कागजों के आधार पर फर्जी समूहों का खाता खुलवाकर पहले शासन से जारी बजट उसमें ट्रांसफर कराया था।

वीडियो रिकॉर्डिंग आन कर सदर क्षेत्र के मगरवारा के युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग आन कर सदर क्षेत्र के मगरवारा के युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। फांसी लगाते हुए उसने आन वीडियो अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी व उसकी बुआ के बेटे सूरज को बताया। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू देख पिता व अन्य स्वजन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दिवंगत की पत्नी रागिनी, फुफेरे साले सूरज, साले रवि राठौर व एक अन्य ससुराल की सोनी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। सदर क्षेत्र के मगरवारा निवासी 28 वर्षीय पवन राठौर की शादी पांच साल पहले कानपुर नगर के बिल्हौर क्षेत्र के उत्तरीपुर गांव में रहने वाली रागिनी से हुई थी। पवन एक होर्डिंग बैनर के कारखाने में नौकरी करता था। बुजुर्ग पिता सुनील राठौर मां मधु और चार साल की बेटी के साथ रहता था। 20 दिन पहले पवन का अपनी पत्नी रागिनी से विवाद हुआ था। इसके बाद रागिनी मासूम बेटी को ससुराल में छोड़कर मायके वालों के साथ चली गई थी। पवन लगातार उसे लाने का प्रयास कर रहा था पर वह नहीं आ रही थी। इससे पवन परेशान चल रहा था। दोपहर लगभग एक बजे पवन कमरे में गया और छत पर पर रखी टिन शेड के पाइप में नायलान की रस्सी बांधकर लटक गया। मौत से पहले उसने अपने मोबाइल को टेबल पर रखकर उसका वीडियो ऑन कर दिया था।

कानपुर में गंगा का जलस्तर कानपुर में फिर बढ़ने लगा जलस्तर 111 मीटर दर्ज किया गया

कानपुर में गंगा का जलस्तर कानपुर में फिर बढ़ने लगा है। सोमवार सुबह 10 बजे शुक्लागंज गेज पर गंगा का जलस्तर 111 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 113 मीटर से महज 2 मीटर नीचे है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने पहले ही गंगा किनारे गांवों अलर्ट जारी किया है, घाटों पर जल पुलिस की तैनाती की गई है। गंगा बैराज में नाव चलाने पर रोक भी लगाई गई है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। गंगा बैराज और नदी किनारे जल पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर नाव संचालन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार सुबह 8 बजे गंगा बैराज से आगे की ओर 1,06,981 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं नरौरा से 53,211 क्यूसेक और हरिद्वार से 66,226 क्यूसेक पानी गंगा में पहुंचा। सिंचाई विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में गंगा में जितना पानी आया, लगभग उतनी ही मात्रा में आगे छोड़ दिया गया, जिससे जलस्तर में फिलहाल नियंत्रित बढ़ोतरी हुई है। रविवार शाम को गंगा बैराज के 30 गेटों का गेज भी बढ़ाया गया था, ताकि बढ़ते जलप्रवाह का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। अब गंगा किनारे रहने वाले लोगों में बाढ़ की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं गंगा बैराज के आसपास बसे 10 से अधिक गांवों के किसानों को नदी किनारे खड़ी फसलों के डूबने का डर सताने लगा है। हालांकि फिलहाल जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से 2 मीटर दूर:गंगा बैराज से 1,06,981 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, 111 मीटर रिकॉर्ड हुआ जलस्तर

पैदल घर जा रही महिला की बाइक सवार दो लुटेरों ने चेन लूट ली

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

दही क्षेत्र के मुहल्ला आवास विकास कालोनी में रविवार शाम छह बजे पार्क से टहलकर पैदल घर जा रही महिला की बाइक सवार दो लुटेरों ने चेन लूट ली। महिला के शोर मचाने पर जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते लुटेरे भाग निकले। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों पर लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर सीसी कैमरों की मदद से जांच शुरू की है।आवास विकास कालोनी के बी-150 में रहने वाली अर्चना दुबे पत्नी दिवंगत दिनेश चंद्र दुबे रविवार 26 जुलाई 2026 की शाम लगभग 6:45 बजे चंद्रशेखर आजाद पार्क, आवास विकास से टहल कर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान रास्ते में बाइक से आए दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। महिला कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और तेज रफ्तार में मौके से भाग निकले। दहशत में पहले तो महिला के मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ संभलने पर शोर मचाया। आसपास मौजूद लोग जब तक उसके पास पहुंचकर माजरा समझते लुटेरे आंखों से ओझल हो गए। पीड़ित महिला अन्य स्वजन के साथ दही थाना पहुंची और घटना की तहरीर दी। एसओ जानेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात बाइक सवार दो लुटेरों के विरुद्ध लूट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। शीघ्र घटना का राजफाश कर आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। सदर क्षेत्र के मुहल्ला कल्याणी देवी निवासी तारा सिंह पत्नी विश्राम सिंह एक जुलाई की रात लगभग आठ बजे हरदोई ओवरब्रिज के नीचे से सब्जी खरीदकर घर जा रही थीं। घर से 100 मीटर पहले एक युवक पीछे से पहुंचा और महिला के हाथ से पर्स छीनकर भाग निकला। महिला के अनुसार पर्स में नौ हजार रुपये व मोबाइल था। रिपोर्ट तो दर्ज हुई पर आज तक घटना का राजफाश नहीं हो सका।

विवाह योजना में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने पटल सहायक को निलंबित कर दिया

उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को दिए गए उपहार में हुई अनियमित के खिलाफ जांच बताई गई थी। जांच मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें एटीएम भी शामिल थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैक लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामग्री वितरण करने में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 24 जुलाई 2026 को आयोजन किया गया था। एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जोड़ों को दिए गए उपहारों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 459 जोड़ों का विवाह हुआ था, जिसमें प्रत्येक जोड़े को दो-दो गद्दे उपहार में दिए जाने थे। कुल 918 गद्दों में से कुछ गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चिन्ह से मिलती-जुलती डिजाइन पाई गई, जिस पर खूब चर्चा हुई। इस संबंध में शिकायत भी की गई। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपायुक्त उद्योग की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। मिली रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर सदर कोतवाली में आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वहीं उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को सामग्री वितरण में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वाराणसी में गौ सम्मान को लेकर संतों का शक्ति प्रदर्शन

5.5 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सरकार को सौंपा

प्रतिनिधियों ने दावा किया कि अभियान के पहले चरण में देशभर की लगभग 5,000 तहसीलों से 5 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र कर सरकार को भेजे गए थे। उनका कहना है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अब दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के समर्थन के साथ दोबारा ज्ञापन भेजा जा रहा है।

वाराणसी में सोमवार को गोसंरक्षण और गोसम्मान से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर साधु-संतों, बटुकों और गोभक्तों ने व्यापक प्रदर्शन किया। 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज, सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान निकाली गई प्रार्थना-यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां अभियान से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने करीब 5.5 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है।अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार से गोमाता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा देने, पूरे देश में गोहत्या पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना जैसी प्रमुख मांगों पर निर्णय लेने की अपील की गई है। इसके अलावा कुल 30 से अधिक मांगों को ज्ञापन में शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य गोसंरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना बताया गया।कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक धार्मिक विधि-विधान के साथ हुई। सबसे पहले गोमाता का पूजन किया गया, जिसके बाद शंखनाद और वैदिक मंत्रों का सामूहिक उच्चारण हुआ। इसके बाद संतों, बटुकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हाथों में झंडे, बैनर और मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर प्रार्थना-यात्रा निकाली। यात्रा में गोमाता को भी शामिल किया गया, जबकि एक बुलडोजर को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की आकर्षक झांकी भी यात्रा का हिस्सा रही, जिसने श्रद्धालुओं और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद संतों और अभियान के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि गोसंरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका कहना था कि सरकार को इस दिशा में दीर्घकालिक और प्रभावी नीति बनानी चाहिए, जिससे गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।अभियान के पदाधिकारियों के अनुसार, पिछले छह महीनों से देशभर में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' चलाया जा रहा है। इसके तहत गोहत्या निषेध के लिए राष्ट्रीय कानून, गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने, केंद्रीय गो मंत्रालय के गठन, गो-चारा नीति लागू करने तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में गो-केंद्रित राष्ट्रीय नीति तैयार करने जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।प्रतिनिधियों ने दावा किया कि अभियान के पहले चरण में देशभर की लगभग 5,000 तहसीलों से 5 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र कर सरकार को भेजे गए थे। उनका कहना है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अब दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के समर्थन के साथ दोबारा ज्ञापन भेजा जा रहा है। वाराणसी से भेजा गया 5.5 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भी इसी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। अब इस अभियान से जुड़े लोगों की निगाहें केंद्र और राज्य सरकार की आगामी प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।

बरेली के कुछ पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में आ गए,वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना फरीदपुर इलाके की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक उप निरीक्षक (दरोगा) निर्माणाधीन दीवार को पैर मारकर गिराते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके साथ मौजूद एक सिपाही फावड़े से दीवार की ईंटें उखाड़ता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला बरेली के ब्लॉक भुता के थाना फरीदपुर इलाके के ग्राम कैरुआ का है। ग्राम निवासी संजय शास्त्री और उनके परिवार के बीच करीब 20 साल पुराने पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी जमीन पर निर्माण कार्य शुरु हुआ तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर सूचना 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शांति भंग की कार्रवाई करते हुए फिलहाल निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पूरी होने के बाद हल्का संख्या-2 में तैनात उपनिरीक्षक परविंदर कुमार एक सिपाही के साथ फिर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने किसी न्यायालय के आदेश, राजस्व विभाग की मौजूदगी या प्रशासनिक अनुमति के बिना निर्माणाधीन दीवार गिरानी शुरु कर दी। वीडियो में उपनिरीक्षक दीवार पर पैर मारते दिखाई दे रहे हैं, जबकि साथ आया सिपाही फावड़े से ईंटें निकालता नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद कुछ गांववालों ने घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो फैलते ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

काम के पहले ही दिन नौकरानी ने फ्लैट से मोबाइल चोरी कर लिया

यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक फेमस सोसाइटी के फ्लैट में काम के पहले ही दिन नौकरानी ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। नौकरानी को पता नहीं लगा लेकिन उसकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी से चोरी का एक मामला सामने आया है। यहां एक नौकरानी ने फ्लैट में काम के पहले ही दिन मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पूरी वारदात फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोप है कि नौकरानी ने मौका मिलते ही मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया और वहां से फरार हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के आधार पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस आरोपी नौकरानी की तलाश में जुटी हुई है। एक बार फिर यह घटना घरों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने और उन्हें रखने से पहले पूरी जानकारी जुटाने की जरूरत को उजागर करती है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि फ्लैट के लिविंग रूम में एक मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। इसी दौरान महिला एक बच्चे को गोद में लिए वहां आती है और फौरन मोबाइल पर हाथ साफ कर देती है। इसके बाद महिला फ्लैट और सोसाइटी से तेजी से बाहर निकलती है। महिला को इस बात की भनक नहीं लगती कि वह चोरी करते हुए फ्लैट के सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। हालांकि अब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। महिला चोर के इस सीसीटीवी को देखकर सोसाइटीवासी भी दंग हैं। घर में आमतौर पर नौकरानी जब काम करती हैं तो उन पर हर समय पैनी नजर रख पाना संभव नहीं होता। ऐसे में अगर कोई महिला नौकरी के पहले ही दिन इस तरह की घटना को अंजाम दे तो बाकी लोगों का भरोसा अपनी नौकरानियों पर जरूर डगमगा जाता है। फिलहाल महिला ने ये चोरी क्यों की और उसने मोबाइल ही क्यों चुराया, ये तो गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ही सामने आ पाएगा। सोसाइटी में ये मामला जरूर चर्चा में बना हुआ है।

जंतर मंतर पर खाना खिलाने वाले जुनैद के घर पहुंच रही पुलिस

दिल्ली के जंतर-मतर पर चले प्रदर्शन के दौरान लगातार सेवादार के रूप में छात्रों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने वाले मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव निवासी मोहम्मद जुनैद मालिक इन दिनों चर्चा में है। लेकिन उनके इस काम की वजह से मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में रहने वाले उनके परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। उनके पिता मुस्तफा का आरोप है कि यूपी पुलिस उनके परिवार और रिश्तेदारों को पूछताछ के नाम पर लगातार परेशान कर रही है। इसकी वजह से जुनैद की मां की तबीयत काफी बिगड़ गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पिछले ये दिनों में उनके घर पहुंचकर पूछताछ की और घरवालों से दस्तावेजों की जानकारी ली। उनके पिता का कहना है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। वह लोगों की सेवा कर रहा है। वह बचपन से ही लोगों की मदद करता आ रहा है। उनके पिता ने बताया कि 23 जुलाई की शाम करीब पांच बजे मसूरी पुलिस उनके घर पहुंचे। पुलिस ने घर में रखे दस्तावेज देखे और जुनैद के पिता मुस्तफा को पूछताछ के लिए थाने ले गई। वहां उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली गई। परिवार का कहना है कि रात करीब 11 बजे उन्हें वापस भेज दिया गया। अगले दिन 24 जुलाई को मुस्तफा को फिर थाने बुलाया गया, जहां पूरे दिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया। दावा है कि 24 जुलाई की सुबह पुलिस मेरठ में जुनैद की बड़ी बहन के ससुराल पहुंची और उनके ससुर से भी पूछताछ की। उनके पिता ने बताया कि हमारा पूरा परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है। जुनैद ने हाल ही में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है।